राजमार्ग पर जान देना और जेब लुटाना

ग्राउंड जीरो से विवेक की विशेष रिपोर्ट

स्मार्ट सिटी फ़रीदाबाद के बीच से गुजरता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो फ़रीदाबाद का चीरहरण करता प्रतीक होता है। इस राजमार्ग से गुजरने पर दोनों तरह के लोग, पैदल पार करने वाले और गाड़ी से चलने वाले असुरक्षित हैं।

सरकारी आंकड़ों की माने तो सराय से बल्लबगढ तक की दूरी में ही औसतन एक व्यक्ति अपनी जान इस रोड पर रोज़ गंवा देता है। जाहिर सी बात है कि इसमें उसकी स्वयं की लापरवाही तो शामिल है ही परन्तु ये नहीं समझा जाना चाहिए कि दुर्घटना का कारण उसका धतूरा खाकर चलना है। बल्कि मौतों का सेहरा सरकारी मशीनरी के सर ही बांधा जाना चाहिये।

बीते कई वर्षों से राजमार्ग को 6 लेन का बनाने का नकली प्रयास जारी है। कई वर्ष तो राजमार्ग को रीकार्पेटिंग करने में ही बीत गये जिसका ठेका मोदी के चहेते सितारों में से एक मध्यम पड़ते सितारे अनिल अम्बानी की रिलायंस कम्पनी ने लिया।

सड़क का जीर्णोधार कार्य 2012 से प्रारम्भ हो गया और उसी के साथ टोल वसूलने की लूट भी बढ़ा दी गयी। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। सड़क जब बनेगी तब बनेगी पैसा पहले ही अम्बानी की जेब में।

बड़ी मशक्कत के बाद सड़क का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है। पर जो टोल पहले 80 रुपये का था अब वह बढकर 150 रुपये हो चुका है। इतना पैसा लुटाने के बाद भी आम नागरिक को क्या मिला यह जानना जरूरी है।

स्मार्ट सिटी फ़रीदाबाद के सराय टोल से ज्यों ही आप आगे बढेंगे तो पायेंगे कि सड़क के दोनो ओर सर्विस रोड से मुख्य रोड के बीच किसी भी प्रकार का अवरोध कई स्थानों पर नदारद है और जहां पर है वहां भी उनका होना नाम मात्र का ही है। अवरोध के रूप में लगायी गयी रेलिंग की ऊंचाई इतनी

ही है कि लोग उसे जब चाहें तब कूद कर बीच हाईवे में आ जायें। इतना ही नहीं रेलिंग की क्वालिटी भी मोदी और खट्टर सरकार जैसी ही नकली है। एक ठोकर और रेलिंग का अस्तित्व समाप्त।

दुर्घटना होने की सूरत में पैदल यात्री तो अपनी जान गंवाता ही है साथ ही वाहन चालक भी जान गवाने की स्थिति में ही होता है। यदि किसी तरह बच भी जाए तो पुलिस एवं अन्य सरकारी मशीनरी उसे जीने नहीं देगी। जबकि टोल की मोटी रकम चुकाने के बाद इस प्रकार के हादसे का जिम्मेवार स्वयं प्रशासन ही है।

सरकारी अनुमान के अनुसार सड़क पूरा होने का काम अभी अन्तिम चरण में ही था कि शहर को मैट्रो की सौगात भी मिल गयी। फ़रीदाबाद वासियों के लिये यह एक वरदान ही था कि शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिये पैदल पारपथ मैट्रो स्टेशन की शक्ल में मुहैया हो सका। वरना निकम्मी और दूरदर्शिता शब्द से अपरिचित सरकारों को ये तक ख्याल नहीं कि नागरिकों को सड़क भी पार करनी होगी।

समस्या का समाधान इतने भर से नहीं होता न ही हो सकता है। मैट्रो स्टेशनों के बीच की दूरी लगभग एक से डेढ़ किलो मीटर है जिस कारण जनता को सड़क बीच में से ही पार करने का जोखिम उठाना पड़ता है। इसी क्रम में तेज रफ़्तार गाड़ी से जान गंवा बैठते हैं। पैदल तो पैदल, श्याम चाट भंडार, सोनू दे मशहूर छोले-कुल्चे, और मोटरसाइकिलों पर लदे तीन-तीन लोग इस तेज रफ़्तार सड़क को पार करने की हिमाकत करते नज़र आते हैं।

सेक्टर 28 से आकर यदि आप हाईवे पर बायें मुड़ना चाहें तो सम्भव ही नहीं है। ऐसा तब है जब चौराहे पर तीन-तीन ट्रैफ़िक पुलिस के जवान काओब्वॉय हैट लगाये सुशोभित हो रहे हैं। बायां मोड़ फ्री होने के बावजूद ऑटो चालकों का पूरा दस्ता सड़क को घेरे खड़ा रहता है। जाहिर है बिना पुलिस की कृपा के उनकी आंखों के सामने ये सम्भव नहीं है।

हाईवे के साथ सर्विस रोड पर लगभग सिर्फ़ एक लेन के अलावा दूसरी कोई जगह नहीं। स्मार्ट सिटी का हवनकुंड बनाने वाले अक्ल की आहुति देकर प्लानिंग करते हैं। मैट्रो को संचालित हुये लगभग तीन वर्ष हो चुके हैं और मैट्रो के नीचे का सारा स्थान उबड़-खाबड़ पड़ा है। इस टूटी सड़क को पक्का रूप देकर सर्विस लेन की चौड़ाई में इजाफ़े के साथ ट्रैफ़िक की बहुत सारी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। वहीं व्यवस्थित ऑटो स्टैंड एवं पार्किंग स्थल बनाये जा सकते हैं। परन्तु ऐसा होने पर अतिक्रमण करा कर अपने जेबें भरने वाले प्रशासन की आमदनी पर चोट हो सकती है।

हाईवे पर ऑफ़िस ऑवर में मेवला महाराजपुर और एनएचपीसी चौक सरीखे औद्योगिक क्षेत्रों के पास से निकलने वाली कामगारों की भीड़ पर हादसे का खतरा बराबर बना रहता है। रेलिंग इतनी घटिया क्वालिटी की लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द टूट जाये और नया टैंडर कर फ़िर रिश्वत खायी जाए।

इस रेलिंग का काम कई महीनों से जारी है और कई सालों तक चलेगा जिस प्रकार इसे लगाया जा रहा है। कायदे से तो रेलिंग लगे बिना सड़क का उद्घाटन ही नहीं होना चाहिये और तय सीमा में सभी कार्य पूरे होने चाहिये। परन्तु टोल की लूट के लिये बिना पूरा कार्य किये इसे लोगों को मरने के लिये खोल दिया गया।

सड़क की दोनों तरफ़ एग्जिट और एन्ट्री गेट दिये गये हैं जिन पर जाम लगना आम बात हो गयी है। बाटा चौक से सराय की तरफ़ जाने पर संकरा सा एन्ट्री गेट है जो गड्ढों से पटा पड़ा है। थोड़ा ही आगे जाने पर नीलम चौक का एग्जिट गेट है जहां सीएनजी पम्प पर गाड़ियों का रेला गैस भरवाने के लिये बेतरतीब खड़ा रहता है। यहां लगने वाले जाम का यह प्रमुख कारण है परन्तु अन्तिम नहीं।

मंगलवार को प्रभु हनुमान के दर्शनों को उमड़ी भीड़ अपनी गाड़ियां हाईवे पर ही पार्क कर देती है। ये भी तब जब बाटा चौक मैट्रो स्टेशन के नीचे ही ट्रैफ़िक पुलिस बूथ है और सड़क की दूसरी तरफ़ हरियाणा पुलिस का मोटर ट्रैफ़िक स्कूल है। सड़क से लगी इस सर्विस लेन पर मंदिर और गड्ढों के अलावा मोटर गैराज और कबाड़ियों का जमावड़ा है। इसी के साथ सर्विस लेन एवं मेट्रो पुल के नीचे मलिक मोटर सरीखे सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीद-फ़रोख्त करने वाले दलालों का कब्ज़ा है।

हर 500 मीटर पर स्वचालित सीढ़ियों वाला पैदल पार पथ, कम से कम छः फ़ीट ऊंची मजबूत रेलिंग, डिवाइडर में साढे तीन फ़ीट ऊंचे सघन पौधे, साइन बोर्ड काले सफ़ेद पेंटेड बॉर्डर रिफलेक्टर इत्यादि लगाये बिना तो किसी भी टोल रोड का शुभारम्भ भी नहीं होना चाहिये। परन्तु स्मार्टनेस का दम्भ भरने वाली मोदी एवं अन्य सरकारें अपनी कमियों को किस स्मार्टनेस के साथ अन्य राजनीतिक दलों पर थोप लेते हैं यही उन से सीखा जा सकता है। इसके अलावा स्मार्टनेस की उम्मीद अपनी मूर्खता का परिचय होगा।

सरकारी मूर्खता एवं जनता से दुश्मनी का बेहतरीन नमूना है मोदी का 'आयुष्मान भारत'

फ़रीदाबाद (म.मो.) मोदी एवं खट्टर सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में तो जनता के लिये कोई ढंग का काम किया नहीं अब चुनाव सिर पर आये तो चिकित्सा सेवा के नाम पर जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिये 'आयुष्मान भारत' के नाम से एक नया पाखंड खड़ा कर दिया है। इसके लिये सरकार ने न तो कोई अस्पताल खोले न डॉक्टरों व स्टाफ़ की संख्या बढाई और न ही डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिये मेडिकल कॉलेज खोले। देश की 50 करोड़ जनता को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा देने के लिये उनका 5 लाख तक का बीमा सरकार करेगी। यानी सरकार देशी- विदेशी बीमा कम्पनियों को बीमा की किश्त दे देगी, उसके बाद बीमा कम्पनी बीमारों का इलाज विभिन्न निजी एवं सरकारी अस्पतालों में करायेगी।

बीमा की किश्तें भरने के लिये हरियाणा सरकार ने 200 करोड़ का बजट बनाया है। इसमें से 80 करोड़ राज्य सरकार व शेष 120 करोड़ केन्द्र सरकार देगी। उसके बाद बीमा कम्पनियां किसका क्या इलाज कहां और कैसे करायेंगी कोई नहीं जानता। यहां गौरतलब बात यह है कि जो हरियाणा सरकार आज इस पाखंड योजना के लिये

बीके अस्पताल में मारमारी के ऐसे दृश्य आम हैं

80 करोड़ रुपये तुर्त-फ़ुर्त बीमा कम्पनियों को देने के लिये तैयार बैठी है लेकिन वह अपनी ईएसआई चिकित्सा सेवा पर खर्च करते रोती है। इस पाखंड योजना पर 80 करोड़ के बदले हरियाणा सरकार को केन्द्र से मात्र 120 करोड़ मिलेंगे जबकि इतनी ही रकम यदि ईएसआई चिकित्सा सेवा के बजट पर खर्च करे तो उसे 560 करोड़ मिलते और यह रकम भी सरकार के अपने हाथ में रहती जिसे वह तार्किक ढंग से चिकित्सा सेवा पर खर्च कर सकती थी जबकि 200 करोड़ की रकम बीमा कम्पनी को देने के बाद राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहता।

दूसरी बड़ी बात यह है कि इस तथाकथित आयुष्मान योजना के तहत राज्य के मात्र 15 लाख लोग ही आते हैं जबकि ईएसआई के तहत 30 लाख परिवार यानी एक करोड़ बीस लाख लोग आते हैं। राज्य एवं ईएसआई की कुल राशि 560+80 यानी 640 करोड़ रुपये से सरकार डिस्पेंसरियां एवं अस्पताल खोल सकती है। डॉक्टर एवं स्टाफ़ भर्ती कर सकती है। आवश्यक उपकरण एवं अन्य साजो सामान तथा दवायें आदि खरीद सकती है। यह सब कुछ सरकार की निगरानी एवं नियंत्रण में होता जबकि बीमा कम्पनियों और निजी अस्पतालों पर सरकार का कोई नियन्त्रण संभव नहीं है।

इस पूरे ड्रामे को सरकार की मूर्खता नहीं तो और क्या कहा जा सकता है? सर्वविदित है कि ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) भी एक बीमा कम्पनी जैसी ही है। अंतर केवल इतना ही है कि यह पूर्णतया सरकारी नियंत्रण में है। इसमें जमा होने वाला सारा पैसा सरकार के नियंत्रण में ही रहता है। सरकार जब चाहे इस पैसे से डिस्पेंसरियां, अस्पताल व मेडिकल कॉलेज आदि बना सकती है। आवश्यकता अनुसार डॉक्टरों व स्टाफ़ की भर्ती कर सकती है। आवश्यकता अनुसार तमाम तरह के उपकरण एवं दवायें आदि खरीद सकती है। इसके विपरीत निजी बीमा कम्पनियों में गया पैसा उनके मुनाफ़े में परिवर्तीत हो जाता है।

दुर्भाग्य की बात है कि ईएसआई निगम में आज लगभग 80 हजार करोड़ रुपया जमा पड़ा है। जनता को बेहतरीन चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने का पाखंड करने वाली सरकारों ने आज तक इस पैसे का कोई सदुपयोग नहीं किया। जो खट्टर सरकार राज्य की मात्र 15 लाख आबादी के लिये 80 करोड़ रुपये बीमा कम्पनियों को देने जा रही है, यदि इस सरकार ने इतना पैसा प्रति वर्ष अपनी ईएसआई हेल्थ केयर में लगाया होता तो आज राज्य की एक करोड़ बीस लाख आबादी को कहीं अधिक बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती थी।

पाठक जान लें कि खट्टर सरकार ईएसआई हेल्थ केयर पर प्रति वर्ष 15-20 करोड़ ही खर्च करती है। परन्तु इन्हें जनता की बेहतरी से कोई लेना-देना नहीं है। इन्हें तो राजनीतिक स्टंटबाज़ी करने का चस्का लगा हुआ है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06